भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3878
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: शिवहर से पीएमएफबीवाई के तहत पंजीकृत किसान

3878. श्रीमती लवली आनंदः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है;

(ख) शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अक्सर प्रभावित होने वाले पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है;

(ग) शिवहर में उक्त अवधि के दौरान कितने दावों का निपटारा किया गया और फसल नुकसान के लिए किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(घ) क्या सरकार फसल नुकसान का आकलन करने के लिए ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है ताकि दावों का तेजी से निपटान हो सके; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): देश में खरीफ 2016 सीज़न से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) राज्यों और किसानों दोनों के लिए स्वैच्छिक है। बिहार सरकार ने प्रारंभ में इस योजना को दो वर्षों, अर्थात् वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए कार्यान्वित किया था और उसके बाद से इसे कार्यान्वित नहीं किया है। यद्यपि, वे अपनी स्वयं की गैर-बीमा, राहत सहायता योजना, "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" कार्यान्वित कर रहे हैं।

PMFBY के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर पर, विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात वर्ष 2022-23 से 2024-25 (खरीफ 2024 तक) के दौरान कुल 3,539 लाख किसान आवेदन नामांकित किए गए हैं।

(घ) और (ङ): इस योजना के अंतर्गत हाल ही

में वर्ष 2023-24 से निष्पक्ष, पारदर्शी और ऑब्जेक्टिव फसल क्षति एवं हानि आकलन की सुविधा के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

i. **यस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली) के** तहत रिमोट सेंसिंग आधारित उपज अनुमान को क्रमिक रूप से अपनाने की कल्पना की गई है ताकि उचित और सटीक फसल उपज अनुमान के साथ-साथ उपज का आकलन करने में सहायता मिल सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूँ की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान में 30% भारांश अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ 2024 सीज़न से इसमें शामिल किया गया है।
ii. **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली) के तहत** ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अति-स्थानीय मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क से पाँच गुना बड़ा स्वचालित मौसम केंद्रों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी (ARG) का नेटवर्क स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतर-संचालन और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में डाला जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए, बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

*****